



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 24(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (23) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(24) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की धारा 14 के उपनियम (2) या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई जांच प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति के साथ नियुक्त किया गया कोई अन्य प्रारंभिक जांच प्राधिकारी।"

[फा. सं. पी.12011 /2/2009-इएस सेल-डीओआर]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सा.का.नि 381 (अ) तारीख 27 जून, 2006 में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 929(अ) तारीख 29 दिसंबर 2009, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 सितंबर, 2010, सा.का.नि. 957(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 735(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2012, सा.का.नि 30(अ) , तारीख 17 जनवरी, 2014, सा.का.नि 564(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 970(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 136(अ), तारीख 17 फरवरी, 2017 और सा.का.नि. 437(अ) तारीख 8 मई, 2018 और सा.का.नि.674(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2019

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (I) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006, namely :-

In the said notification, after serial number (23) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

“(24) An inquiry authority appointed under sub-rule (2) of rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850) and any other preliminary enquiry authority appointed with concurrence of the Central Vigilance Commission, by the Disciplinary Authority, with the prior approval of the Central Government.”.

[F. No. P.12011/2/2009-ES Cell-DOR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 929(E), dated the 29th December 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010, G.S.R. 957(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 735(E), dated the 1st October, 2012, G.S.R. 30(E), dated the 17th January, 2014, G.S.R. 564(E), dated the 6th August, 2014, G.S.R. 970(E), dated the 15th December, 2015, G.S.R. 136(E), dated the 17th February, 2017, G.S.R. 437(E), dated the 8th May, 2018 and G.S.R. 674(E), dated the 25th July, 2018.